



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 206

दि. 30.04.2026,

गुरुवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल में मतदान का महाआयोजन: 90% के पार पहुंची भागीदारी ने रचा नया इतिहास

कोलकाता। लोकतंत्र के पर्व में पश्चिम बंगाल ने इस बार जो तस्वीर पेश की है, उसने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस तरह से यहां मतदान के आंकड़े लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह केवल चुनावी उत्साह है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक और राजनीतिक चेतना काम कर रही है। बुधवार 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही यह लगभग तय हो गया है कि इस बार राज्य में मतदान का प्रतिशत 90 के आंकड़े को पार कर जाएगा, जो अब तक के इतिहास में अभूतपूर्व माना जा रहा है।

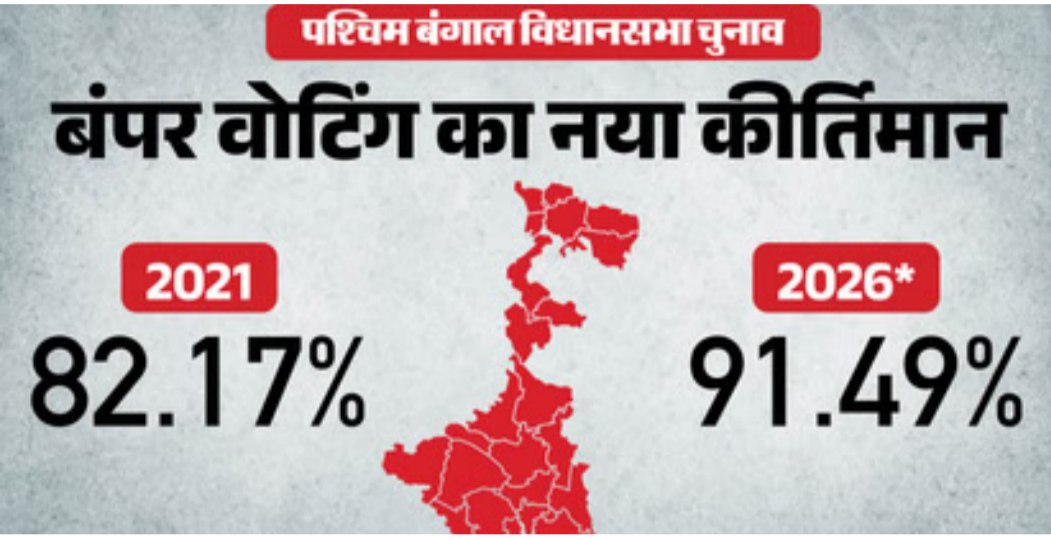
वैश्विक भूख संकट की भयावह तस्वीर: 47 देशों में करोड़ों लोग भूखमरी की चपेट में, पाकिस्तान सबसे प्रभावित देशों में शामिल

नई दिल्ली। दुनिया एक ऐसे मानवीय संकट की ओर बढ़ रही है, जहां विकास और तकनीकी प्रगति के बीच भी करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। Global Report on Food Crises 2026 की ताजा रिपोर्ट ने इस कठोर सच्चाई को उजागर किया है कि वर्ष 2025 में 47 देशों में करीब 26.6 करोड़ लोग भूखमरी से प्रभावित रहे। यह आंकड़ा वर्ष 2016 की तुलना में लगभग दोगुना है, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित देशों में पाकिस्तान भी शामिल है, जहां हालात विशेष रूप से चिंताजनक बने हुए हैं। पाकिस्तान में लगभग 1.1 करोड़ लोग भूख से प्रभावित हैं, जिनमें से 93 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 17 लाख लोग ऐसे हैं जो आपात स्थिति में हैं, जहां भोजन की उपलब्धता बेहद सीमित है और जीवन बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। यह स्थिति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों की रोजमर्रा की त्रासदी बन चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में इस संकट के पीछे कई कारण एक

हैं। इस तरह दोनों चरणों का औसत मतदान 90 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है, जो न केवल पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा है, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों के रिकॉर्ड को भी चुनौती देता नजर आ रहा है। अब तक सबसे ज्यादा मतदान का राष्ट्रीय रिकॉर्ड त्रिपुरा के नाम रहा है, जहां 2013 में 91.82 प्रतिशत मतदान हुआ था, लेकिन बंगाल इस आंकड़े को भी पार कर सकता है। इस चुनाव में कुल 1,448 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं। लेकिन नतीजों से पहले जिस चीज ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, वह है मतदाताओं की अभूतपूर्व भागीदारी। यह भागीदारी केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि राज्य के लोग अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को लेकर पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुके हैं। अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों से तुलना की जाए तो यह बदलाव और

दिल्ली नगर निगम में भाजपा का परचम: प्रवेश वाही बने महापौर, आप के बहिष्कार के बीच एकतरफा जीत

रास्ता आसान किया, वहीं दूसरी ओर इसने यह भी दिखाया कि नगर निगम की राजनीति में अब केवल पारंपरिक प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि और चयनात्मक भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि, आप ने यह स्पष्ट किया है कि वह पूरी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया से अलग नहीं हो रही है। पार्टी ने संकेत दिया है कि वह नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में भागीदारी करेगी। यह समिति नगर निगम के प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए यहां पर आप की सक्रियता आने वाले समय में नई राजनीतिक रणनीतियों को जन्म दे सकती है। दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र में नगर निगम की सत्ता पर पकड़ मजबूत करना की राजनीति में केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक सकारात्मक संकेत है। यह जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक साबित हो सकती है और आगामी चुनावों के लिए नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। वहीं, कांग्रेस के लिए यह परिणाम कठमों का भी परिणाम है। आम आदमी पार्टी के बहिष्कार ने जहां एक ओर भाजपा के लिए



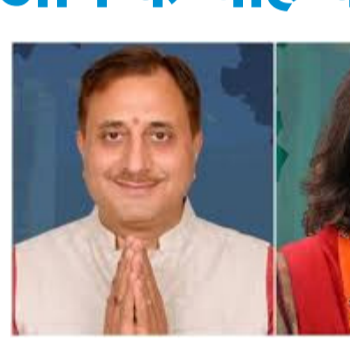
भी स्पष्ट नजर आता है। 2011 में, जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ था और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को समाप्त किया था, उस समय मतदान का प्रतिशत 84.33 था, जो उस दौर का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। उससे पहले 1996 और 2006

उत्तरे में मतदान 80 प्रतिशत के पार गया था, लेकिन 90 प्रतिशत के आंकड़े को छूने की बात तो दूर, उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया था। यही कारण है कि 2026 का यह चुनाव एक नई समय मतदान का प्रतिशत 84.33 था, जो उस दौर का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। उससे पहले 1996 और 2006

उत्तरे में मतदान 80 प्रतिशत के पार गया था, लेकिन 90 प्रतिशत के आंकड़े को छूने की बात तो दूर, उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया था। यही कारण है कि 2026 का यह चुनाव एक नई समय मतदान का प्रतिशत 84.33 था, जो उस दौर का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। उससे पहले 1996 और 2006

90 प्रतिशत के पार पहुंच गया है। यदि समान सीटों पर तुलना की जाए तो यह अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। 2021 में जिन सीटों पर पहले चरण में 83.18 प्रतिशत और दूसरे चरण में 81.08 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं 2026 में उन्हीं सीटों पर यह आंकड़ा क्रमशः 93.19 और 90 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से भी यह चुनाव रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। 2021 में जहां राज्य में कुल 7.34 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, वहीं इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद यह संख्या घटकर 6.82 करोड़ रह गई। इसके बावजूद मतदान करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इस बार अब तक 6.25 करोड़ से अधिक लोग अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक है। यह इस बात का संकेत है कि मतदाता सूची में कमी के बावजूद लोगों की भागीदारी में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें और वृद्धि हुई है।

उपमहापौर दोनों पदों के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसके पार्षदों ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। सभी मतों को वैध घोषित किया गया, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की पुष्टि हुई। परिणाम सामने आने पर यह स्पष्ट हो गया कि मुकाबला एकतरफा रहा। प्रवेश वाही को कुल 156 मत प्राप्त हुए, जबकि जहीर को मात्र नौ मतों से संतोष करना पड़ा। इस तरह 147 मतों के विशाल अंतर से जीत दर्ज करते हुए प्रवेश वाही ने न केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक प्रभाव को भी मजबूती से स्थापित किया। यह चुनाव ऐसे समय में हुआ जब नगर निगम की राजनीति पहले से ही काफी गर्माई हुई थी। विभिन्न दलों के बीच खींचतान और रणनीतिक असमानता का भी प्रतीक है। यदि इस चुनौती का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं।



उपमहापौर दोनों पदों के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसके पार्षदों ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। सभी मतों को वैध घोषित किया गया, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की पुष्टि हुई। परिणाम सामने आने पर यह स्पष्ट हो गया कि मुकाबला एकतरफा रहा। प्रवेश वाही को कुल 156 मत प्राप्त हुए, जबकि जहीर को मात्र नौ मतों से संतोष करना पड़ा। इस तरह 147 मतों के विशाल अंतर से जीत दर्ज करते हुए प्रवेश वाही ने न केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक प्रभाव को भी मजबूती से स्थापित किया। यह चुनाव ऐसे समय में हुआ जब नगर निगम की राजनीति पहले से ही काफी गर्माई हुई थी। विभिन्न दलों के बीच खींचतान और रणनीतिक असमानता का भी प्रतीक है। यदि इस चुनौती का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं।

हो और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। इसके बावजूद, यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल ने इस बार लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जो उदाहरण पेश किया है, वह प्रेरणादायक है। यह केवल एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक संदेश बन गया है कि जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, तो वे किस तरह इतिहास रच सकते हैं। अब सबकी नजरें आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि इतनी भारी मतदान का असर किसके पक्ष में जाता है। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हों, यह स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा। पश्चिम बंगाल ने यह दिखा दिया है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी ही उसकी असली ताकत होती है।

कोलहापुर ब्लैकमेलिंग कांड पर सख्त एक्शन: राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट, बड़े गिरोह की आशंका

नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र के कोलहापुर से सामने आए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस गंभीर प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और राज्य पुलिस को तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इस मामले को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला एक 22 वर्षीय फार्मसी छात्र से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि आरोपी ने पहले उनसे दोस्ती और विश्वास का संबंध बनाया, फिर उनका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता पैदा करती हैं। आयोग ने इस घटना को महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर गंभीर प्रहार करार दिया है। आयोग की अध्यक्ष ने महाराष्ट्र पुलिस को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि मामले में कठोर

कोलहापुर ब्लैकमेलिंग कांड पर सख्त एक्शन: राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट, बड़े गिरोह की आशंका

नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र के कोलहापुर से सामने आए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस गंभीर प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और राज्य पुलिस को तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इस मामले को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला एक 22 वर्षीय फार्मसी छात्र से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि आरोपी ने पहले उनसे दोस्ती और विश्वास का संबंध बनाया, फिर उनका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता पैदा करती हैं। आयोग ने इस घटना को महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर गंभीर प्रहार करार दिया है। आयोग की अध्यक्ष ने महाराष्ट्र पुलिस को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि मामले में कठोर



धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। इसमें भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की सख्त धाराओं को लागू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आयोग ने इस पूरे मामले को केवल एक व्यक्ति की करतूत मानने से इनकार किया है और इसके पीछे बड़े आपराधिक नेटवर्क की आशंका जताई है। आयोग का मानना है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया, वह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आए इसी तरह के एक मामले ने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह समस्या कहीं अधिक व्यापक हो सकती है, जिसके भीतर उन्हें इस पूरे मामले

को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कितने पीड़ितों की पहचान की गई है, मुख्य आरोपी के अलावा किन-किन लोगों की भूमिका सामने आई है और आगे की जांच किस दिशा में बढ़ रही है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी पीड़ितों को उचित सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे बिना किसी डर के न्याय की प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से पालन और समय पर कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। यह मामला प्रशासन, समाज और तकनीकी प्लेटफॉर्म सभी के लिए एक चेतावनी है कि वे इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अधिक सक्रिय रहें। सितलहाल, इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्ती से यह उम्मीद जगी है कि जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट यह तय करेगी कि पोर्नोग्राफी वेबसाइट या डार्क वेब पर भी साझा किए गए हैं। यदि ऐसा पाया जाता है, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस को स्पष्ट रूप से सात दिन की समयसीमा दी है, जिसके भीतर उन्हें इस पूरे मामले

को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कितने पीड़ितों की पहचान की गई है, मुख्य आरोपी के अलावा किन-किन लोगों की भूमिका सामने आई है और आगे की जांच किस दिशा में बढ़ रही है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी पीड़ितों को उचित सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे बिना किसी डर के न्याय की प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से पालन और समय पर कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। यह मामला प्रशासन, समाज और तकनीकी प्लेटफॉर्म सभी के लिए एक चेतावनी है कि वे इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अधिक सक्रिय रहें। सितलहाल, इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्ती से यह उम्मीद जगी है कि जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट यह तय करेगी कि पोर्नोग्राफी वेबसाइट या डार्क वेब पर भी साझा किए गए हैं। यदि ऐसा पाया जाता है, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस को स्पष्ट रूप से सात दिन की समयसीमा दी है, जिसके भीतर उन्हें इस पूरे मामले

CHENNAL NO. 2063

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

गर्मी की छुट्टियों में मनोरंजन के साथ-साथ विज्ञान भी सीखेंगे गुजरात के बच्चे, 'गुजकोस्ट' द्वारा समर साइंस कैंप 2026 का आयोजन

▶▶ राज्य में स्थित चार क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों में 1 से 30 मई, 2026 के दौरान विभिन्न बैच में 3 दिवसीय समर साइंस कैंप आयोजित होंगे

▶▶ कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए आयोजित इस समर कैंप में विज्ञान आधारित 5 आकर्षक थीम को कवर किया जाएगा

▶▶ समर कैंप में छात्रों को नमो सरस्वती विज्ञान साधना और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी

गांधीनगर : गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम संस्थान गुजरात कार्डसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (GUJCOST- गुजकोस्ट) राज्य भर में विज्ञान विषय की शिक्षा और विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। राज्य के आम लोगों, विशेषकर छात्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाने और समझ विकसित

करने के उद्देश्य से गुजकोस्ट द्वारा पाटण, भावनगर, राजकोट और भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों (आरएससी) की स्थापना की गई है। ये केंद्र आज विज्ञान विषय की जिज्ञासा को शांत करने तथा व्यावहारिक शिक्षा एवं साइंस टूरिज्म के वाइब्रेंट केंद्र के रूप में उभरे हैं। गुजकोस्ट ने गर्मियों की छुट्टियों को बच्चों के लिए और आकर्षक बनाने तथा उन्हें मनोरंजन के साथ विज्ञान की शिक्षा देने के लिए एक नई पहल की है। विज्ञान



GUJARAT COUNCIL ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department of Science and Technology, Government of Gujarat
www.gujcost.gujarat.gov.in

विषय में रुचि रखने वाले बच्चों के साथ-साथ अन्य बच्चों में भी विज्ञान के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के उद्देश्य से गुजकोस्ट ने आगामी 1 से 30 मई के दौरान राज्य में स्थित चारों क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों में अलग-अलग बैच में 3 दिवसीय रोजेंडेशनल समर साइंस कैंप का आयोजन किया है। इस समर कैंप को कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए

डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक बैच में अधिकतम 50 छात्र शामिल हो सकते हैं। इस कैंप के दौरान विज्ञान आधारित पांच आकर्षक थीम को कवर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान और आभिव्यक्ति की भूमिका पर बल देते हुए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय

अनुसंधान' का अपडेटेड राष्ट्रीय नारा दिया है। उन्होंने कहा है, "विज्ञान भारत के भविष्य के विकास और नवाचार के केंद्र में है। विज्ञान आविष्कार, क्रमिक विकास और नवाचार का आधार है।" मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि गुजरात के अधिक से अधिक छात्रों को विज्ञान में दिलचस्पी पैदा हो। आज, जब गुजरात सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और डिजिटल साइंस जैसे क्षेत्रों का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब भविष्य में इन क्षेत्रों के लिए कुशल तकनीकी कार्यबल की बड़े पैमाने पर मांग पैदा होगी। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक छात्र कक्षा 11 और 12 में विज्ञान संकाय का चुनाव करें। गुजकोस्ट द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन यह सुनिश्चित करना कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र विज्ञान विषय में रुचि लें और आगे जाकर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में सोचें।

समर साइंस कैंप 2026 में पांच आकर्षक थीम को कवर किया

जाएगा कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए आयोजित किए गए इस समर कैंप में छात्रों के लिए रुचिकर पांच आकर्षक थीमों को कवर किया गया है। इनमें वैज्ञानिक कैसे बनें, स्पेस (अंतरिक्ष) समर कैंप, मरीन बायोलॉजी/मशीन इंजीनियरिंग, एआई और रोबोटिक्स तथा एक्सप्लोरिंग नेचर यानी प्रकृति के तत्वों की खोज जैसे थीम शामिल हैं। समर साइंस कैंप के दौरान छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जिनमें व्यावहारिक प्रयोग, विज्ञान प्रदर्शनी, मल्टीमीडिया सत्र, नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन (रात्रिकालीन खगोलीय अवलोकन), फील्ड विजिट, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान से जुड़े खेल और वॉक-थ्रू इन गैलरी आदि शामिल हैं। ये गतिविधियां बच्चों को मनोरंजन के साथ विज्ञान से परिचित कराएंगीं। छात्रों को दी जाएगी नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के बारे में जानकारी समर साइंस कैंप के दौरान छात्रों को

विज्ञान विषय के विशेषज्ञों के साथ बातचीत और चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा। इसके अलावा, कैंप के दौरान बच्चों को नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मैरिट स्कॉलरशिप योजना और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मैरिट स्कॉलरशिप योजना जैसी राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ-साथ भावी करियर के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के छात्रों को कक्षा 11 और 12 में विज्ञान संकाय में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना लागू की है। राज्य के सरकारी या अनुदानित स्कूलों में कक्षा 5 की पढ़ाई पूरी करने वाले 2,00,000 प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विभिन्न स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मैरिट स्कॉलरशिप योजना तथा राज्य के सरकारी या शिक्षा का अधिकार

(आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कक्षा-1 से 8 तक पढ़ाई पूरी करने वाले 1,00,000 प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विभिन्न स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मैरिट स्कॉलरशिप योजना लागू की गई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की शिक्षा अधूरी न रह जाए। गुजकोस्ट द्वारा समर साइंस कैंप की इस पहल का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मकता बढ़ाना, स्टैम (एसटीईएम- साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) करियर को बढ़ावा देना तथा छात्रों और विज्ञान के बीच एक स्थायी संबंध स्थापित करना है। इस कैंप में छात्रों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कैंप में हिस्सा लेने के इच्छुक छात्र और उनके अभिभावक अपने क्षेत्र के निकट स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जम्मू मण्डल में इंजीनियरिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

उत्तर रेलवे के जम्मू मण्डल में इंजीनियरिंग कार्य के कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। विवरण निम्नानुसार है-

शॉर्ट ओरिजिनेट/शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेनें
▶▶ ट्रेन संख्या 19415 साबरमती-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक अमृतसर स्टेशन पर

शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी।
▶▶ ट्रेन संख्या 19416 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-साबरमती एक्सप्रेस 02 जून 2026 तक अमृतसर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस 14 जून 2026 तक फिरोजपुर कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 19224 जम्मू तवी-साबरमती एक्सप्रेस 15 जून 2026 तक फिरोजपुर कैंट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस-एमसीटीएम ऊधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक पूर्णतः निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 19108 एमसीटीएम ऊधमपुर-भावनगर टर्मिनस जन्मभूमि एक्सप्रेस 01 जून 2026 तक पूर्णतः निरस्त रहेगी।
ट्रेनों के उधराव, संरचना एवं समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

गुजरात से 73 लाख से अधिक यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेनों में किया सफर महिलाओं की रही पहली पसंद, 722 करोड़ से अधिक का राजस्व किया अर्जित

भारतीय रेलवे की प्रीमियम सेमी-हाईस्पीड सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस ने देश में आधुनिक रेल यात्रा की नई पहचान स्थापित की है। फरवरी 2019 में एक सेवा से शुरू होकर आज यह नेटवर्क देशभर में 162 से अधिक ट्रेनों तक विस्तारित हो चुका है, जो प्रमुख शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा से जोड़ रहा है। गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने यात्रियों के बीच विशेष लोकप्रियता हासिल की है। 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि में राज्य से संचालित 6 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों में लगभग 73 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जबकि इनसे कुल 722 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। गुजरात से 6 संचालित वंदे भारत ट्रेनों का विवरण (आरंभ तिथि सहित)



▶▶ साबरमती - वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 27 मई 2025
▶▶ असारवा - उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 18 फरवरी 2026
अहमदाबाद-मुंबई मार्ग पर दोनों वंदे भारत सेवा यात्रियों की पहली पसंद बन चुकी है। पेशेवर, व्यवसायिक तथा नियमित यात्री इस सेवा का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। इन सेवाओं में न केवल यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, बल्कि कई मार्गों पर मांग क्षमता से कहीं अधिक, 140% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है, यह

लोकप्रियता को दर्शाती है। कुछ मार्गों पर ऑक्यूपेंसी 100% से अधिक रही है, जबकि कुछ ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी 90% से अधिक रही है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनें 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत निर्मित वंदे भारत ट्रेनें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें शामिल हैं:

▶▶ स्वचालित दरवाजे एवं जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली
▶▶ आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें एवं

पर्याप्त लेगरूम
▶▶ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं ऑनबोर्ड इन्फोटेनमेंट
▶▶ पूर्ण सीसीटीवी कवरेज एवं बायो-वैक्यूम शौचालय
▶▶ दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय
▶▶ ट्रेनें में अग्निशामक यंत्र और फायर अलार्म की व्यवस्था
▶▶ उल्कूप्ट खान-पान एवं सेवाएं
यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की ऑनबोर्ड सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें:

▶▶ स्वच्छ एवं ताजा भोजन
▶▶ क्षेत्रीय स्वाद पर आधारित विविध मेन्यू
▶▶ प्री-पैकड हाइजीनिक सेवा
▶▶ प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सम्यक् सेवा एवं उच्च समयपालन, बेहतर सुरक्षा मानक एवं उल्कूप्ट स्वच्छता के कारण यात्रियों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। तेज गति और कम यात्रा समय के कारण ये ट्रेनें व्यवसायिक एवं अवकाश यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस की यह उल्लेखनीय सफलता भारतीय रेल के यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण का सशक्त प्रमाण है। भारतीय रेल भविष्य में भी यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमृत भारत स्टेशन ने बदली भारतीय रेल की तस्वीर, इंफ्रा के कार्यों ने बढ़ाई रेल की गति

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इंजीनियरिंग, ट्रेक अनुसंधान, संरचना सुदृढ़ीकरण तथा यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वडोदरा मंडल के 5 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। मंडल द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से न केवल रेल संचालन में संरक्षा और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है, बल्कि यात्रियों को भी बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री सुमित ठाकुर ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 मई, 2025 को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 किलोमीटर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल (TSR) कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं।



ब्रिज कार्यों के अंतर्गत 15 पुलों का निर्माण किया गया। 5 पुलों का री-गर्डीनिंग तथा 33 पुलों पर एप्रोच ट्रांजिशन कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 906 स्टील चैनल स्लीपरों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे पुलों की संरचनात्मक मजबूती

सुनिश्चित हुई है। स्टेशनों याई सुधार कार्यों के अंतर्गत 9 याई में 14 लेआउट का सुधार किया गया, 972 लेआउट का मानकीकरण किया गया तथा विभिन्न तकनीकी उन्नयन कार्य जैसे TWS और WCMSC का समावेशन किया गया। 68 याई में PRL लाइनों का उन्नयन किया गया तथा 2472 स्थानों पर फ्री जॉइंट्स का उन्मूलन किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OMS) में 0.15g से अधिक मान में 93.25% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिससे ट्रेक की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। डेरैल स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज (FOB) तैयार किया गया है तथा अन्य 8 स्टेशनों पर भी 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (FOB) के विकास कार्य प्रगति पर हैं। मंडल ने 20 प्लेटफार्मों

का विस्तार एवं उन्नयन, 13 स्टेशनों पर कोचिंग ऑपरेशन पैनल (COP) की सुविधा, 3 नए 06 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज FOB का निर्माण तथा 9 स्टेशनों पर कवर शेड का निर्माण किया है। इसके अलावा स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, रैप, भूमिगत मार्ग आदि, 47 स्टेशनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है और स्टाफ के लिए 104 नए रेलवे आवासों का निर्माण किया गया है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से वडोदरा मंडल ने रेलवे अवसरंचना को सुदृढ़ करते हुए सुरक्षित, तेज एवं आरामदायक रेल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपायविधियां हासिल की हैं। पश्चिम रेलवे भविष्य में भी इसी प्रकार की विकासत्मक पहलों के माध्यम से यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा।

धूप से निखार तक: सन टैन हटाने के असरदार घरेलू उपाय-शहनाज हुसैन

गर्मियों की तेज धूप त्वचा पर सबसे पहले असर दिखाती है और यही वजह है कि इस समय में सन टैन एक आम समस्या बन जाती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, धूल-प्रदूषण और पसीना मिलकर त्वचा की रंगत को प्रभावित करते हैं, जिससे चेहरा सांवला, बेजान और थका हुआ दिखने लगता है। कई लोग इससे बचने के लिए महंगे कॉस्मेटिक उत्पादों का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर ये हर स्किन टाइप के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऐसे में प्राकृतिक और घरेलू उपाय न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि लंबे समय तक त्वचा को पोषण भी देते हैं। भारतीय व्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन भी हमेशा प्राकृतिक उपायों को प्राथमिकता देने की सलाह देती रही हैं।



पपीता सन टैन हटाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इसमें मौजूद एंजाइम त्वचा की डेड सेल्स को हटाकर उसे चमकदार बनाते हैं। पके हुए पपीते को मैश करके उसमें कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर चेहरे पर लगाने से धीरे-धीरे टैन कम होने लगता है। यदि इसमें शहद मिला दिया जाए तो यह त्वचा को नमी भी देता है और चेहरा मुलायम बनता है। नियमित इस्तेमाल से त्वचा में प्राकृतिक ग्लो लौट आता है। नींबू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। एक चम्मच नींबू का रस, शहद और दूध मिलाकर बनाया गया फेस पैक त्वचा की रंगत निखारने में मदद करता है। दूध में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को टोन करते हैं, जबकि शहद उसे हाइड्रेट रखता है। वहीं नींबू और चीनी का मिश्रण हल्के स्क्रब की तरह काम करता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाकर नई त्वचा को उभरने का मौका देता है। लेकिन ध्यान रखें कि नींबू का उपयोग संवेदनशील त्वचा पर सावधानी से करें। खीरा गर्मियों का सबसे ठंडक देने वाला प्राकृतिक उपाय है। इसमें भरपूर पानी होता है, जो त्वचा को हाइड्रेट करता है और जलन को शांत करता है। खीरे का रस, गुलाब जल और नींबू मिलाकर कॉटन से चेहरे पर लगाने से टैन धीरे-

धीरे हल्का होने लगता है। इसके अलावा खीरे, पपीते, दही और ओट्स का मिश्रण भी त्वचा को गहराई से साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। यदि खीरे और ओट्स भी त्वचा की सफाई और टैन हटाने में मददगार हैं। जई के आटे में मठा मिलाकर लगाया गया पेस्ट त्वचा की गंदगी को हटाता है और उसे फ्रेश बनाता है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी त्वचा पर धूप का असर ज्यादा होता है। केला, शहद और ऑलिव ऑयल का मिश्रण त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ उसकी रंगत सुधारने में भी मदद करता है। केला त्वचा को साफ बनाता है, शहद नमी बनाए रखता है और ऑलिव ऑयल त्वचा को गहराई से पोषण देता है। यह पेक सूखी त्वचा वालों के लिए खासतौर पर लाभकारी है। एलोवेरा त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद गुण त्वचा को ठंडक देते हैं और टैन को धीरे-धीरे कम

करते हैं। एलोवेरा जेल में हल्दी और शहद मिलाकर लगाने से त्वचा साफ और चमकदार बनती है। अगर रोजाना सिर्फ एलोवेरा जेल भी लगाया जाए तो त्वचा की रंगत में सुधार दिखने लगता है। बेंसन और दही का पारंपरिक नुस्खा भी आज तक उतना ही असरदार है। इसमें हल्दी मिलाकर लगाने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और टैन कम पड़ता है। यह मिश्रण त्वचा को प्राकृतिक तरीके से निखार देता है और किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कुछ लोग शहद, संतरे का रस और अंडे के सफेद हिस्से का फेस पैक भी इस्तेमाल करते हैं। यह त्वचा को टाइट करने के साथ-साथ उसे ग्लोइंग बनाता है। वहीं दही और नींबू का मिश्रण भी त्वचा को साफ और फ्रेश रखने में मदद करता है। आलू का रस भी टैन हटाने में काफी लोकप्रिय घरेलू उपाय है। इसमें प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो त्वचा

के दाग-धब्बों और टैन को हल्का करने में सहायक होते हैं। कदकस किए हुए आलू का रस चेहरे पर लगाकर कुछ देर बाद धोने से त्वचा साफ और चमकदार दिखने लगती है। इन सभी उपायों के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि आप धूप में निकलते समय अपनी त्वचा की सुरक्षा का ध्यान रखें। हल्के कपड़े, स्कार्फ, सनस्क्रीन और पर्याप्त पानी का सेवन आपकी त्वचा को अंदर और बाहर दोनों तरह से सुरक्षित रखता है। घरेलू नुस्खे तभी असर दिखाते हैं जब उन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए और त्वचा के अनुसार सही उपाय चुना जाए। गर्मियों में सन टैन से पूरी तरह बचना मुश्किल जरूर है, लेकिन सही देखभाल और प्राकृतिक उपायों की मदद से इसे कम किया जा सकता है। ये घरेलू नुस्खे न केवल आपकी त्वचा को टैन से राहत देते हैं, बल्कि उसे स्वस्थ, मुलायम और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत भी बनाते हैं।

पश्चिम रेलवे चलाएगी हावड़ा के लिए चार वन-वे स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा के लिए भुज, साबरमती, वटवा एवं राजकोट से हावड़ा के लिए चार वन-वे स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. ट्रेन संख्या 09401 भुज - हावड़ा वन-वे स्पेशल
ट्रेन संख्या 09401 भुज-हावड़ा जंक्शन वन-वे स्पेशल दिनांक 30 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को पुनः से 15:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 17:25 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में गांधीधाम, भचाऊ, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदिकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में महेशाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदिकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, मजिदपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर, शिवसागर रोड, भागलपुर, कहलगाँव, साहिबगंज, न्यू फरका, मालदा टाउन, आजीमगंज, कटवा, नवद्वीप धाम एवं बंडेल स्टेशनों पर उठरेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, द्वितीय श्रेणी चेयरकार तथा सामान्य श्रेणी कोच रहेंगे।



हावड़ा वन-वे स्पेशल
ट्रेन संख्या 09403 साबरमती-हावड़ा जंक्शन वन-वे स्पेशल दिनांक 01 मई 2026 (शुक्रवार) को वटवा से 16:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 16:15 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में महेशाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदिकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, मजिदपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर, शिवसागर रोड, भागलपुर, कहलगाँव, साहिबगंज, न्यू फरका, मालदा टाउन, आजीमगंज, कटवा, नवद्वीप धाम एवं बंडेल स्टेशनों पर उठरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर, द्वितीय श्रेणी चेयरकार तथा सामान्य श्रेणी कोच रहेंगे।
3. ट्रेन संख्या 09481 वटवा - हावड़ा वन-वे स्पेशल
ट्रेन संख्या 09481 वटवा-हावड़ा वन-वे स्पेशल दिनांक 01 मई 2026 (शुक्रवार) को वटवा से 16:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 10:00 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन छायापुरी, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बिना, वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, जानपुर रोड, बनारस, वागणसी, दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल तथा दुर्गापुर स्टेशनों पर उठरेगी।

हावड़ा वन-वे स्पेशल
ट्रेन संख्या 09501 राजकोट - हावड़ा वन-वे स्पेशल
ट्रेन संख्या 09501 राजकोट-हावड़ा जंक्शन वन-वे स्पेशल दिनांक 30 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को राजकोट से 17:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 19:10 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में वानकाण, सुरेंद्रनगर, महेशाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदिकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, मजिदपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर, शिवसागर रोड, भागलपुर, कहलगाँव, साहिबगंज, न्यू फरका, मालदा टाउन, आजीमगंज, कटवा, नवद्वीप धाम एवं बंडेल स्टेशनों पर उठरेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, द्वितीय श्रेणी चेयरकार तथा सामान्य श्रेणी कोच रहेंगे। ट्रेनों के समय, उधराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

एग्जिट पोल के उलझे संकेत: कहीं 'कमल' की बढ़त, कहीं वापसी की उम्मीद, नतीजों से पहले सियासी सस्पेंस चरम पर

कोलकाता। पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल सामने आते ही देशभर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आंकड़े इतने उलझे हुए हैं कि तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो गई है। कहीं भारी बहुमत के दावे हैं तो कहीं वापसी की उम्मीदें, और कुछ जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबले ने पूरी कहानी को ही अनिश्चित बना दिया है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक, सभी की नजरें अब 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं, जो इन तमाम दावों और अनुमानों की असली परीक्षा होगी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां एग्जिट पोल पूरी तरह बंटे हुए नजर आ रहे हैं। आठ प्रमुख सर्वे में से छह में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि लंबे समय से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस को इस बार सत्ता से बाहर होना पड़ सकता

है। कुछ सर्वे तो भाजपा को 178 से 200 से अधिक सीटें तक दे रहे हैं, जो राज्य में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। दो एग्जिट पोल ऐसे हैं जो पूरी तरह अलग कहानी पेश कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस की शानदार वापसी का दावा कर रहे हैं। इन सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी को 180 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इन विरोधाभासी आंकड़ों ने बंगाल को सबसे रोमांचक और अनिश्चित मुकाबले में बदल दिया है, जहां किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां के एग्जिट पोल एक तरह से सियासी पहली बन गए हैं। ज्यादातर सर्वे द्रविड़ मुनेत्र कडमम गठबंधन की वापसी का दावा कर रहे हैं और उसे बहुमत के पार दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ सर्वे पूरी तरह उलट तस्वीर पेश



कर रहे हैं और एनडीए को बढ़त देते दिखा रहे हैं। इस सबके बीच सबसे बड़ा दिक्कत अभिनेता विजय की पार्टी तमिलनाडु वेत्री कथमम ने दिया है। कुछ एग्जिट पोल में यह पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई गई है कि

वह 'किंगमेकर' ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभर सकती है। खासकर कुछ सर्वे में टीवीके को 90 से अधिक सीटों का अनुमान दिया गया है, जिससे यह साफ है कि तमिलनाडु में इस बार मुकाबला परंपरागत दलों

से आगे निकलकर एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर में असम की तस्वीर अपेक्षाकृत साफ नजर आ रही है। यहां सभी 11 एग्जिट पोल एक सुर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रचंड जीत

का दावा कर रहे हैं। 126 सीटों वाली विधानसभा में लगभग हर सर्वे भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें दे रहा है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इन आंकड़ों में काफी पीछे नजर आ रही है और कई सर्वे में उसे 25 से 35 सीटों के बीच सिमटता दिखाया गया है। इन रुझानों से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि असम में भाजपा की पकड़ और मजबूत हो सकती है। वहीं केरल में बदलाव की लहर नजर आ रही है। आठ में से सात एग्जिट पोल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की वापसी का संकेत दे रहे हैं। यह गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है और सर्वे के अनुसार उसे स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। दूसरी ओर, सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिकांश सर्वे एलडीएफ को बहुमत से काफी पीछे दिखा रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि केरल

की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन के मूड में हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश पुद्चेरी में तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है। यहां के सभी प्रमुख एग्जिट पोल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देते नजर आ रहे हैं। कई सर्वे में एनडीए को 20 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है, जो उसे आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचाता है। कांग्रेस गठबंधन यहां काफी पीछे नजर आ रहा है और अन्य दलों का प्रभाव भी सीमित दिख रहा है। इन सभी राज्यों के एग्जिट पोल एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि देश की राजनीति इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। जहां कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल हैं, वहीं कुछ जगहों पर मौजूदा सरकारों की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एग्जिट पोल के ये आंकड़े अंतिम नहीं होते। पिछले कई चुनावों में यह देखा गया है कि एग्जिट पोल

और वास्तविक नतीजों में बड़ा अंतर हो सकता है। इस बार भी बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विरोधाभासी आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि अंतिम परिणाम पूरी तरह अलग भी हो सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां अंतिम फैसला केवल मतदाताओं के वोट से होता है, न कि किसी सर्वे या अनुमान से। 4 मई को जब मतगणना होगी, तब यह साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किसके दावे सही साबित होंगे। फिलहाल, एग्जिट पोल ने सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। राजनीतिक दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, समर्थक जश्न की तैयारी में जुट गए हैं, और विरोधी खेमों में रणनीति बनाने का दौर जारी है। लेकिन असली तस्वीर अभी पढ़ने के पीछे है, जो मतगणना के दिन ही सामने आएगी। तब तक के लिए यह 'गोल-गोल' एग्जिट पोल ही देश की राजनीति में रोमांच और उत्सुकता बनाए हुए हैं।

जैविक खाद में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूरत के किसान का यज्ञ : 'धनजीवामृत' का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया

1 मई को सूरत में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के पहले दिन 'रासायनिक खाद में आत्मनिर्भरता : खाद क्षेत्र में आयात के विकल्प की रणनीतियाँ' विषय पर चर्चा आयोजित होगी, जिसमें कमलेश पटेल सहभागी होंगे

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए कमलेश पटेल रोज 1000 लीटर जीवामृत भी तैयार कर बेचते हैं और 1000 (एक बैग का वजन 40 किलो) धनजीवामृत तैयार करते हैं

राज्य में 8 लाख से अधिक किसान रासायनिक खाद का त्याग कर संपूर्ण प्राकृतिक की ओर मुड़े हैं

गांधीनगर : समग्र राज्य में हाल में गर्मी का पारा 44 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ऐसे समय में सूरत के मांगरोडिया गाँव में कमलेश पटेल के खेत में 20 से अधिक मजदूर खरीफ मौसम से पहले प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए 'धनजीवामृत' बनाने में व्यस्त हैं। सूरत जिले की पलसाणा तहसील के अंधेरी गाँव के किसान कमलेश पटेल प्राकृतिक खेती करते हैं। इतना ही नहीं, वे देश में रासायनिक खाद का आयात कम हो तथा उसके सुदृढ़ विकल्प के रूप में धनजीवामृत तैयार कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती का प्रचार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाते हैं। कमलेश पटेल भी मास्टर ट्रेनर हैं तथा अनेक किसानों को प्राकृतिक खेती करने की प्रेरणा देते हैं।

राज्य में हाल में 8 लाख से अधिक किसानों ने रासायनिक खाद को त्याग कर संपूर्ण प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े हैं। साढ़े पाँच हेक्टेयर से अधिक जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ने से रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में जीवामृत तथा धनजीवामृत का उपयोग होता है और उसकी माँग लगातार बढ़ रही है।

आगामी 1 मई को सूरत में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के पहले दिन 'रासायनिक खाद में आत्मनिर्भरता : खाद क्षेत्र में आयात के विकल्प की रणनीतियाँ' विषय पर चर्चा होगी। कमलेश पटेल इस चर्चा में सहभागी होंगे।

वर्ष 2017 से प्राकृतिक खेती कर रहे कमलेश पटेल ने धनजीवामृत का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया है। वे प्रतिदिन 1000 बैग (एक बैग का वजन 40 किलो) तैयार करते हैं और समग्र राज्य तथा राज्य से बाहर उसकी बिक्री करते हैं। उन्होंने चालू वर्ष में दैनिक 2000 बैग तैयार करने का लक्ष्य रखा है।



गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में प्राकृतिक खेती का विस्तार हो रहा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य के गाँव-गाँव जा रहे हैं और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के फलस्वरूप, किसान रासायनिक खादों का उपयोग बंद कर उसके विकल्प के रूप में जीवामृत व धनजीवामृत का जैविक खाद के रूप में उपयोग कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ये खाद जमीन में सुधार लाते हैं, खेत में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं, जमीन के पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं।

चालू वर्ष में एक लाख बैग धनजीवामृत बनाने का लक्ष्य कमलेश पटेल ने कहा, "अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। उन्हें जीवामृत व धनजीवामृत की जरूरत पड़ती है। गत वर्ष हमने

50,000 थैलियाँ (40 किलो की एक थैली) बेची थीं और इस वर्ष एक लाख धनजीवामृत की थैली का उत्पादन करने की योजना है।"

सुभाष पालेकर के तीन दिवसीय सेमिनार ने जीवन का मार्ग बदला वर्ष 2016 में कमलेश पटेल ने सुभाष पालेकर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'जीरो बजट प्राकृतिक खेती' संबंधी सेमिनार में भाग लिया था तथा वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उसी क्षण उन्होंने रासायनिक खाद को त्याग दिया तथा प्राकृतिक खेती का मार्ग अपनाया।

प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक लोगों ने प्रेरणा दी

वर्ष 2017 में कमलेश पटेल को गन्ने की खेती में प्राकृतिक खेती से उत्तम परिणाम प्राप्त हुए। गन्ने का प्रति बीघा उत्पादन 45 टन हुआ। यह चमत्कार देखकर गाँव के किसानों ने भी इस पद्धति को अपनाने

की तैयारी दर्शाई, लेकिन उनके पास जीवामृत व धनजीवामृत नहीं था। वे इन्हें बनाने के इंग्रट में पड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए किसानों ने कमलेश पटेल को इन दोनों उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रेरणा दी और कमलेश पटेल ने जीवामृत तथा धनजीवामृत का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। गुजरात सरकार ने उनकी आर्थिक सहायता भी की। हाल में कमलेश पटेल दैनिक औसत 40,000 किलो धनजीवामृत तथा 1,000 लीटर जीवामृत तैयार कर बेचते हैं। वे धनजीवामृत 6 रुपए प्रति किलो तथा जीवामृत 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जीवामृत बनाने के लिए उन्हें बायो रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) के लिए सब्सिडी दी जाती है। कृषि विभाग ने धनजीवामृत बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता की है।

सूरत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को 10-20-30 वर्षों से उच्च वेतन लाभों से वंचित रखने का मुद्दा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम में कार्यरत कई सफाई कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी और सूरत नगर निगम में कार्यरत वे कर्मचारी जो 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं और जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है, उन्हें 10 वर्ष पूरे होने पर उच्च वेतन का लाभ दिया जाता है। हाल ही में संशोधित नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी 10, 20, 30 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है, उन्हें 10, 20, 30 वर्ष पूरे होने पर उच्च वेतन का लाभ दिया जाता है। सूरत नगर निगम के कई कर्मचारी 10, 20, 30 वर्षों से उच्च वेतन के लाभ से वंचित हैं। ऐसे कर्मचारियों की कोई शिकायत नहीं सुनी जाती। और जब कर्मचारी अधिकारों के पास जाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि "अभी हमारे पास बहुत काम है। समय आने पर हम



काम करेंगे। हमारे पास मत आइए।" इस तरह के जवाब क्लक (ईसी) कर्मचारियों द्वारा दिए जाते हैं। सूरत नगर निगम में क्लकों के 700 से 800 पद रिक्त हैं। और ये पद वर्षों से भरे नहीं गए हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लिपिकीय कर्मचारियों पर काम का बोझ अधिक होता है। लेकिन 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा

के लिए उच्च वेतन के लाभ के हकदार कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करना किस हद तक उचित है? गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव ने मांग की है कि सूरत नगर निगम के उच्च अधिकारी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दें।

संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के उल्लंघन के आरोप, रैलियों पर प्रतिबंध और लोकतंत्र के मुद्दे पर विवाद

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में, "भाषण की स्वतंत्रता आदि से संबंधित भारत के नागरिकों के कुछ अधिकारों का संरक्षण" शीर्षक के अंतर्गत, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी कहा गया है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है। विपक्षी दलों द्वारा आयोजित रैलियों के विरुद्ध गुजरात भाजपा सरकार की पुलिस की कार्रवाई भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूर्णतः उल्लंघन है। पुलिस द्वारा विभिन्न बहाने बनाकर विपक्षी दलों को सभा या रैली आयोजित करने की अनुमति न देना भी संविधान के नियमों के विरुद्ध है। महात्मा गांधी, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते थे, ने कहा था, "राज्य बलपूर्वक जनता को नियंत्रित करता है, इसलिए हिंसा



ही राज्य के अस्तित्व का आधार है।" मोदी सरकार ने टॉलरेंटिय के इस कथन को अक्षरशः आत्मसात कर लिया है। राज्य का विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। जब जनता को लगता है कि उनके द्वारा चुने गए लोग जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है। और यही

लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन मोदी सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं करती। पिछले 12 वर्षों के शासनकाल से यह सिद्ध हो चुका है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें मोदी सरकार ने पुलिस की क्रूरता और लाठीचार्ज से आंदोलनों को कुचल दिया है, जिनमें किसान आंदोलन एक उदाहरण है।

गुजरात के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा एवं सुविधा का समन्वय

प्रथम चरण में गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका तथा डांग जिलों में टूरिस्ट-फ्रेंडली वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष टूरिस्ट पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे

इस पहल का उद्देश्य मात्र कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि गुजरात की यात्रा पर आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को एक सुरक्षित तथा टूरिस्ट-फ्रेंडली वातावरण प्रदान करना है : डॉ. के. एल. एन. राव

टूरिस्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों के लिए विशेष यूनिफॉर्म डिजाइन करने पर भी चर्चा हुई

पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक जानकारी तथा सुरक्षा संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सेंट्रल इंटरैक्टिव टूरिस्ट पुलिस एप्लिकेशन' विकसित की जाएगी

राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

गांधीनगर : गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा तथा सुखद अनुभव में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) सहित गिर सोमनाथ, द्वारका तथा डांग जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पुलिस महानिदेशक (डीजी) तथा पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के अनुसार राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन जिलों में समर्पित 'टूरिस्ट पुलिस स्टेशन' कार्यरत करना है। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में पहले चरण में गिर सोमनाथ, देवभूमि



द्वारका तथा डांग जैसे प्रमुख पर्यटन जिलों में टूरिस्ट-फ्रेंडली वातावरण सुनिश्चित

करने के लिए विशेष टूरिस्ट पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे।

जिन पर्यटन स्थलों पर पहले से जो पुलिस चौकियाँ कार्यरत हैं, वहाँ उपलब्ध

संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग कर उन्हें अत्याधुनिक टूरिस्ट पुलिस थाने के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। पर्यटक पुलिस को आसानी से पहचान सकें तथा सहायता प्राप्त कर सकें; इसके लिए पुलिस कर्मचारियों के लिए विशेष यूनिफॉर्म बनाने तथा वाहनों के लिए एक अनन्य 'लोगो' डिजाइन करने पर भी बैठक में चर्चा की गई। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की त्वरित सहायता के लिए कंटेनर आधारित डॉक द्वारा 'हेल्प डेस्क' तथा 'कीयोस्क' भी स्थापित किए जाएंगे। पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक जानकारी तथा सुरक्षा संबंधी सेवाएँ मुहैया कराने के उद्देश्य से सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को एक सेंट्रल 'इंटरैक्टिव टूरिस्ट पुलिस एप्लिकेशन'

विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस बैठक में हर टूरिस्ट पुलिस स्टेशन में पर्याप्त संख्या में मानव बल, नए वाहनों की खरीदारी तथा आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि गुजरात की यात्रा पर आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को एक सुरक्षित तथा मैत्रीपूर्ण (टूरिस्ट-फ्रेंडली) वातावरण प्रदान करना है। राज्य पुलिस विभाग द्वारा आगामी समय में इस आयोजन को वेग देने के लिए गुजरात के पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर अधिक सुरक्षित बनाने की मंशा व्यक्त की गई है।